बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए बेहतर करें सिस्टम

राष्ट्रीय अजजा आयोग के चेयरमैन ने मंत्रालय में ली बैठक

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

बैकलॉग पदों पर भर्ती को लेकर सरकार के रवैये से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी खुश नहीं है। आयोग के चेयरमैन डॉ रामेश्वर उरांव ने अफसरों से दो टूक कहा- बैकलॉग के खाली पदों को भरने के लिए सिस्टम को बेहतर करने पर ध्यान दें। प्रदेश में अजजा की शिक्षा को लेकर भी कारगर कदम उठाए जाएं। प्रदेश के दौरे पर आए उरांव ने शुक्रवार को मंत्रालय में समीक्षा बैठक ली।

संगठन भी गुस्साए

बैकलॉग के पदों पर भर्ती नहीं होने से आरक्षित वर्गों से जुड़े कर्मचारी संगठन भी गुस्साए हैं। अजाजजा परिसंघ, अजाक्स समेत अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने उरांव को बैकलॉग की स्थिति के बारे में जानकारी दी। विपिन टोप्पो एवं विजय शंकर श्रवण का कहना है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है।

5वीं, 8वीं फिर से बोर्ड होंगी

बैठक में मौजूद स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने उरांव को बताया कि प्रदेश में 5वीं व 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा खत्म करने से पढ़ाई पर विपरीत असर हो रहा है। इन कक्षाओं को फिर से बोर्ड परीक्षा के दायरे में लाया जाएगा।

लॉ कॉलेज खोलने की सिफारिश

उरांव ने प्रदेश के झाबुआ में लॉ कॉलेज खोलने की सिफारिश भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए।

दो साल से जेल में हैं।

गांधी एसीएस खांडेकर के पर्सनल स्टाफ में पदस्थ

भोपाल | सामान्य प्रशासन विभाग ने स्टाफ ऑफिसर एसके गांधी को एसीएस दीपक खांडेकर की निजी स्थापना में पदस्थ किया है। इसी तरह अजीत राय को आयुष विभाग की प्रमुख सचिव शिखा दुबे की निजी स्थापना में भेजा गया है। एलडी सांवनेर उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आशीष उपाध्याय तथा जगन्नाथ जाटव पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव अश्विनी राय की निजी स्थापना में पदस्थ हुए हैं।

सौजन्य भेंट

भोपाल। राज्यपाल रामनरेश यादव से केन्द्रीय अनुसूचति जन-जाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को राजभवन में सौजन्य भेंट की।

'जनजाति के उत्थान के लिए सरकार संवेदनशील है'

सीएम ने की अनुसूचित जनजाति आयोग से चर्चा

प्रशासनिक संवाददाता ■ भोपाल

राज्य मंत्रालय में शुक्रवार को पांचवी मंजिल पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दल के साथ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह , एसीएस एसआर मोहंती सहित अन्य वरिष्ठ अफसरों से चर्चा हुई। मंत्रालय में करीब तीन घंटे चली इस गोपनीय बैठक में मंत्री ज्ञान सिंह ने दल को जनजातीय समुदाय के अधिकारों के संरक्षण और उनसे जुड़े विकास की बातें बताई। जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने प्रदेश में जनजातियों से जुड़ी योजनओं की जानकारी ली। बैठक के बार उरांव राजभवन के लिए रवाना हुए तथा वहां राज्यपाल से मुलाकात कर उनकी सेहत की जानकारी ली। इसके बाद वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास गए, जहां मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं साथ ही कई नई योजनाएं भी वर्तमान में चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उरांव को बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने अध्यक्ष को बताया कि जनजाति समुदाय के बच्चों को प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। हर साल पचास बच्चों को उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए विदेशी संस्थानों में भी भेजा जा रहा है।

बैकलॉग के पद नहीं भरने से आयोग खफा

दो घंटे में ढेरों कमियां गिना गए उरांव, राज्य सरकार को किया कठघरे में खड़ा

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
editor@peoplessamachar.co.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने 8 सालों से बैकलॉग पदों के नहीं भरे जाने पर नाराजगी जताई है। उनकी नाराजगी इस बात को भी लेकर थी कि छानबीन समिति के निर्णयों पर विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। अलीराजपुर में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी का नाम लेकर कहा कि छानबीन समिति के निर्णय के बाद वह हाईकोर्ट से स्टे ले आया और दो-दो जिलों का प्रभारी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखें।

आदिवासी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे कामों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सवाल खड़े किए हैं। आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने मोदी सरकार का नाम लिए बगैर कहा कि बीते दो सालों में आदिवासी क्षेत्रों में कोई चमत्कार नहीं हुआ है।

बैठक में गिनाई ढेरों कमियां: आयोग के अध्यक्ष उरांव ने शुक्रवार को मंत्रालय में अफसरों की बैठक ली। दो घंटे की इस बैठक में अध्यक्ष ने आदिवासियों के लिए चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में ढेरों कमियां गिनाई। उन्होंने आदिमजाति कल्याण विभाग की ओर से आदिवासी विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं का सही से क्रियान्वयन न होने पर नाराजगी जताई है। वे विभाग की ओर से रखे गए आंकड़ों से भी नाखुश नजर आए हैं। उधर, विभाग के मंत्री ज्ञान सिंह ने आयोग की नाराजगी को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि आयोग के सुझावों पर अमल कर सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

सीएम ने गिनाई सफलताएं

आदिवासियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के बाद आयोग के अध्यक्ष उरांव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। चौहान ने आयोग के अध्यक्ष से जनजातीय कल्याण के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के अधिकारों के संरक्षण और उनसे जुड़े विकास के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। इसके लिए कई नवाचारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। चौहान ने यह भी बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया है।

राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भोपाल में, ली अफसरों की क्लास

बर्खास्तगी के बाद कैसे आया सोमकुंवर

ीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने आबकारी विभाग में बने
ायक आयुक्त सोमकुंवर की दर्जनों शिकायतों को लेकर अफसरों की
ास ली। वे यहां तक बोले कि वह बर्खास्त होने के बाद वापस कैसे आ गया।

भूमि न्यूज, भोपाल

र्जी जाति प्रमाण-पत्र से आबकारी विभाग सहायक आयुक्त बने सोमकुंवर मामले में ीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर व ने मंत्रालय के अफसरों की जमकर ास ली। उन्होंने कहा कि छानबीन समिति नब प्रमाण-पत्र फर्जी करार दिया है, ऐसे में र्बास्तगी के बाद वह कैसे वापस आ गया। एडी ने कोर्ट में ठीक से पक्ष क्यों नहीं रखा। ांव ने और भी कई मामलों में जमकर टकार लगाई।

अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय ध्यक्ष उरांव अपने दो दिनी दौरे पर मप्र ए हुए थे। उनके साथ आयोग के उपाध्यक्ष ठाकुर और सचिव एके अग्रवाल भी थे। योग ने झाबुआ जिले का सघन दौरा का दिवासियों के लिए चलाई जाने वाली जनाओं, अत्याचार निवारण अधिनियम, ाधिकार पट्टा, पानी, आरक्षण जैसे मुद्दों पर हां के लोगों से मिलकर उनकी स्थिति जानी। उरांव को झाबुआ में ढेरों शिकायते मिली थी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित छानबीन समिति में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मुद्दे पर उन्होंने खासतौर पर जानकारी ली। उनके सामने अलीराजपुर व झाबुआ जिले के आबकारी आयुक्त सोमकुंवर की दर्जनों शिकायतें मिली थी। सूत्रों ने बताया कि झाबुआ जिले के हर दिन कई ट्रक अवैध शराब गुजरात पहुंच रहा है। उन्हें झाबुआ में अन्य जगहों पर भी इस तरह की गंभीर शिकायत मिली। एक शिकायत यह भी थी कि जब से सोनकुंवर पदस्थ हुए हैं, तभी से इसमें खासी बढ़ोतरी हो गई है। झाबुआ जिले की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है।

खास बातें

- सोमकुंवर मामले में ठीक से पैरवी नहीं करने पर जताया असंतोष
- बोले जीएडी ने कोर्ट में ठीक से क्यों नही रखा अपना पक्ष
- छानबीन समिति के निर्णय पर कार्रवाई नहीं होने पर भी बिफरे

क्यों पैरवी में हुई लापरवाही

उरांव ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अफसरों से पूछा कि 6 साल पहले बर्खास्त होने के बाद कोर्ट के आदेश पर यह फिर से बहाल कैसे हो गए। इसमें जीएडी ने कोर्ट में ठीक से पैरवी क्यों नहीं की। बताते हैं कि उस वक्त जीएडी के प्रमुख सचिव के. सुरेश थे। उस दौरान के अधिकारियों ने कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की, इससे सोमकुंवर को राहत मिल गई थी। इसके बाद उसने विभागीय अफसरों से मिलीभगत कर फिर से बहाल हो गया। शुक्रवार को इस मुद्दे पर अध्यक्ष उरांव ने जीएडी अफसरों की जमकर क्लास ली।

शिक्षक नहीं तो पढ़ाई कैसे

उरांव ने समीक्षा के दौरान पूछा कि जब अंग्रेजी, गणित व विज्ञान के अध्यापक ही नहीं हैं तो आगे की पढ़ाई कैसे होगी। इस हालत पर जनजाति के छात्र आगे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने आदिमजाति कल्याण व शिक्षा विभाग की इस लापरवाही पर खासी नाराजगी जताई। उन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम, वनाधिकार पट्टा व बैकलॉग पदों को नहीं भरने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में पद रिक्त हैं पर आदिवासियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है।

मुख्यमंत्री से भी मुलाकात......

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से राष्ट्रीय जन-जाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की।

खाद्य विभाग की शिकायत

झाबुआ दौरे के समय उन्हें यह भी शिकायत मिली कि आदिवासियों को दो-दो महीने बाद राशन मिलता है। उन्हें नियमित खाद्यान्न नहीं मिलता। सेल्समेनों के काफी पद रिक्त हैं, किंतु अभी तक नियुक्ति नहीं की जा रही है। इस तरह की शिकायतों पर उन्होंने व्यवस्था दुरुस्त कराने को कहा। इसी तरह पेयजल की शिकायत पर उन्होंने व्यवस्था सुधारने को कहा।

अफसरों का रवैया गैरजिम्मेदाराना

उरांव ने अधिकारियों से पूछा कि छानबीन समिति ने सैकड़ों लोगों के जातिप्रमाण पत्र फर्जी होने पर निरस्त कर दिया, किंतु आज तक एक भी मामले में कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया है, तो ऐसे में प्रदेश के अफसरों का रवैया बेहद गैरजिम्मेदाराना है।